# यह है मनोहर की मनोहारी नगरिया तू देख बबुआ: त्रिलोचन

## गंदगी के ढेर पर बसा सीएम सिटी का प्रशासनिक मुख्यालय

**करनाल ( म.मो. )** कहां तो तैयारी थी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की और बचा नहीं पहले जैसा भी। इस शहर का शुमार राज्य के साफ़-सुथरे शहरों में होता रहा है। यहां के विधान सभा सीट से विधायक बने मुख्यमंत्री खट्टर ने इसे देश के उन 100 शहरों में स्थान दिला दिया जिन्हें स्मार्ट बनाने पर हजारों -करोड़ रुपया खर्च होने वाला था। बीते करीब 6 साल से अन्य शहरों की भांति यहां पर भी हजारों करोड़ रुपया, शहर की स्मार्टनेस पर खर्च किया जा चुका है। लेकिन परिणाम, शहर बद से भी बद्तर हो गया।

शहर की दुर्दशा जानने के लिये पूरे शहर का दौरा करने की जरूरत नहीं है। इसका अनुमान ज़िले के उस प्रशासनिक परिसर को देख कर ही लगाया जा सकता है जहां ज़िले के डीसी, एसपी व तमाम प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं। इस परिसर में जिधर देखो कूड़े-कचरे के ढेर नजर आते हैं। वाहन पार्किंग स्थल भी कूड़े से भरा है, सीवर गट में कूड़ा भरा होने की वजह से जाम पड़ा है। ई-टॉयलेट्स

कमीशनखोरी के लिये खरीद तो लिये लेकिन उन पर ताले लगा कर, शो-पीस की तरह खड़ा कर दिया गया है। परिसर में जो दो-चार टॉयलेट चालू भी हैं वे इस कदर सड़ांध मार रहे हैं कि उनके पास से गुजरना भी अखरता है।

कांग्रेसी नेता त्रिलोचन सिंह इस बदहाली के पीछे अन्य अनेक कारणों के अलावा सफाई कर्मचारियों के दुरुपयोग को भी मानते हैं। उनके अनुसार जिन कर्मचारियों को सार्वजनिक स्थलों की सफाई के लिये तैनात किया गया है, वे बड़े अफ़सरों, जजों तथा राजनेताओं के घरों पर काम करते देखे जा सकते हैं। जाहिर है कि जब प्राथमिकता सार्वजनिक स्थलों की न होकर निजी घरों की हो जाय तो शहर भर की दुर्दशा होना तो तय है ही।

गौरतलब है कि करनाल शहर को सीएम सिटी का दर्जा प्राप्त है। स्थानीय विधायक होने के नाते मनोहर लाल खट्टर ने यहां पर अपना एक आवास भी बना रखा है। इसमें उनका कैंप कार्यालय चलाने के लिये उनका स्टाफ भी बैठता है। कहने को तो यह स्टाफ जनता की समस्यायें सुन कर उन्हें हल करवाता है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। वास्तव में यहां तैनात कारिंदे महज सत्ता के दलाल बनकर रह गये हैं।

# जुझारु डॉक्टरों के सामने खट्टर पड़े लाचार

**रोहतक, खानपुर, करनाल, नूंह ( म.मो. )** हरियाणा सरकार की नई 'बांड पालिसी' के खिलाफ़ प्रदेश के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों का आन्दोलन दिन ब दिन तेज हो रहा है। 25 दिन से चले आ रहे छात्रों के आन्दोलन के समर्थन में तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी तथा वार्ड सेवायें बंद कर दी हैं। तमाम

मरीज अस्पताल छोड़कर भागने को मजबूर हैं। छात्रों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वे आंदोलन और तेज करते हुए आपातकालीन सेवायें भी बंद कर देंगे।

कहने को हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरा करने के मकसद से एमबीबीएस व पीजी छात्रों के लिये नई 'बांड पालिसी' लागू की है, जो सरासर झूठ है। वास्तव में यह बांड पालिसी न होकर फीस पालिसी है। इस पालिसी के मुताबिक छात्रों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने पर हर साल दस लाख रुपये भरने होंगे। इसके लिये छात्रों को सरकार और बैंक के साथ एक बांड साइन करना होगा। बांड के मुताबिक जो छात्र सात साल तक हरियाणा सरकार की नौकरी करेंगे और उनका बैंक लोन सरकार भरेगी जो एक बहकावा है। क्योंकि सरकार नौकरी की कोई गारंटी नहीं दे रही है। बांड तोड़ने की सूरत में छात्रों को 45 लाख रुपये ब्याज सहित बैंक में भरने होंगे। ब्याज की दर क्या होगी यह कोई नहीं बता रहा।

छात्रों का कहना है कि बांड स्टूडेंट और सरकार के बीच होना चाहिये न कि बैंक के माध्यम से। वास्तव में बांड सरकार और छात्र के बीच एक अनुबंध होता है। जिसमें निश्चित समय अवधि तक सरकार की नौकरी से इन्कार करने पर निर्धारित राशि छात्र को जमा करनी होती है। गौर करने लायक बात यह है कि गुजरात में भी 40 लाख रुपये का बांड सीधे सरकार के साथ है। यह राशि भी उस डॉक्टर को भरनी होगी जो एक साल सरकार की नौकरी से इनकार करे। दाखिले के समय वहां यह रकम नहीं ली जाती। बाकी देश के किसी भी राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं है।

दरअसल ये 'बांड पालिसी' नहीं है, खट्टर द्वारा ईजाद की गई लूट पालिसी है। उन्हें शायद इस बात से बड़ी तकलीफ होती होगी कि डॉक्टर बनने के बाद लोग अच्छा-खासा कमाने लगते हैं तो क्यों न उनसे एडवांस में ही फ़ीस के नाम पर वसूली कर ली जाय।